



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

22 पौष 1944 (श0)
(सं0 पटना 54) पटना, वृहस्पतिवार, 12 जनवरी 2023

सं० 2/आरोप-01-40/2015-23031/सा0प्र0
सामान्य प्रशासन विभाग

अधिसूचना

21 दिसम्बर 2022

श्री अनिल कुमार (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 971/11, तत्कालीन अंचलाधिकारी, बोधगया के विरुद्ध राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 1292 दिनांक 04.11.2015 द्वारा आरोप-पत्र गठित कर उपलब्ध कराया गया।

श्री कुमार के विरुद्ध आरोप है कि :-

जिला पदाधिकारी, गया के पत्रांक 1902/भू0सु0 दिनांक 10.08.1994 एवं पत्रांक 1636/भू0सु0 दिनांक 30.08.1994 द्वारा कुल-07 फर्जी विदेशी संस्थाओं का निबंधन एवं दाखिल खारिज पर रोक लगाते हुए सृजित जमाबंदी को रद्द करने का आदेश दिया गया था। साथ ही तत्कालीन जिला पदाधिकारी, गया के उक्त निदेश के आलोक में तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी, सदर गया के ज्ञापांक 971 दिनांक 15.07.2003 एवं अंचल अधिकारी के ज्ञापांक 479 दिनांक 16.07.2003 द्वारा उक्त जमाबंदी रद्द किया गया।

परंतु उक्त आदेशों के द्वारा फर्जी संस्थाओं के नाम से दाखिल खारिज पर रोक लगाने के बावजूद भी श्री कुमार, तत्कालीन अंचलाधिकारी, बोधगया द्वारा अपने पत्रांक 496 दिनांक 30.11.2007 द्वारा उक्त आदेशों की समीक्षा किए बिना रद्द किये जमाबंदी को पुनः कायम करने का निदेश संबंधित राजस्व कर्मचारी को दिया गया, जिसके आलोक में संबंधित राजस्व कर्मचारी द्वारा पुनः रद्द जमाबंदी को कायम किया गया।

श्री कुमार के विरुद्ध आरोप एवं इससे संबंधित सम्पूर्ण वस्तुस्थिति के समीक्षोपरांत आरोप की वृहत जाँच हेतु विभागीय संकल्प ज्ञापांक 16736 दिनांक 10.12.2019 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित किया गया, जिसमें आयुक्त, मगध प्रमंडल, गया को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

आयुक्त कार्यालय, मगध प्रमंडल, गया के पत्रांक 1017/विधि दिनांक 13.03.2021 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया, जिसमें साक्ष्य के अभाव में आरोपी पदाधिकारी के विरुद्ध आरोप को अप्रमाणित प्रतिवेदित किया गया।

अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन से असहमत होते हुए विभागीय पत्रांक 6888 दिनांक 09.07.2021 द्वारा संचालन पदाधिकारी को अग्रेतर जाँच करने का अनुरोध किया गया। उक्त के आलोक में आयुक्त कार्यालय, मगध प्रमंडल, गया के पत्रांक 1767/विधि दिनांक 09.05.2022 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया, जिसमें साक्ष्य के अभाव में आरोपी पदाधिकारी के विरुद्ध आरोप को अप्रमाणित प्रतिवेदित किया गया। जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत जाँच प्रतिवेदन से असहमत होते हुए विभागीय पत्रांक 10591 दिनांक 28.06.2022 द्वारा श्री कुमार से असहमति के बिन्दु पर लिखित अभ्यावेदन की मांग की गयी। श्री कुमार के पत्रांक 843/आ0प्र0 दिनांक 09.07.2022 द्वारा लिखित अभिकथन समर्पित किया गया।

अपने लिखित अभिकथन में श्री कुमार का कहना है कि इनके द्वारा रूट इन्स्टीट्यूट के आवेदन पर तत्कालीन जिला पदाधिकारी द्वारा रसीद निर्गत करने के दिए गए निर्देश, **CWJC No. 4235/2001** में पारित आदेश, उक्त भूमि का अपील या पुनरीक्षण में जमाबंदी रद्द नहीं होने, भूमि का रैयती होने, संस्था का उक्त भूमि पर दखल कब्जा एवं भूमि का बाउण्ड्री वाल के रूप में संस्था का कब्जा रहने तथा संस्था का पूर्णतः भारतीय एवं फर्जी नहीं रहने के आधार पर पूर्णतः समीक्षा कर केवल राजस्व हित में रसीद निर्गत करने का निर्देश दिया गया था। यह इनके पत्र से भी स्पष्ट है। रूट इन्स्टीट्यूट, बोधगया की भूमि का तत्कालीन भूमि सुधार उप समाहर्ता द्वारा अपील वाद सं० 3/88-89 एवं तत्कालीन अंचलाधिकारी द्वारा विविध वाद सं०-11/2002-03 द्वारा जमाबंदी कायम करने का आदेश दिया गया तथा उक्त आदेश के विरुद्ध राजस्व अधिनियम के प्रावधानों के तहत जमाबंदी रद्द करने का कोई भी आदेश सक्षम प्राधिकार द्वारा पारित नहीं किया गया है। यही कारण है कि उक्त भूमि का जमाबंदी आज भी कायम है तथा लगान रसिद निर्गत हो रहा है। इन्होंने जांच के दौरान साक्ष्य परीक्षण हेतु विविध वाद सं०-11/2002-03 एवं इनके द्वारा दिये गये आदेश की मूल संचिका की मांग की गई, जो नैसर्गिक न्याय के तहत उपलब्ध कराया जाना चाहिए था, लेकिन उसे नहीं उपलब्ध कराया गया। इनका 2009 में उक्त अंचल से स्थानान्तरण के बहुत दिन बाद 2015 में इन पर इस मामले में आरोप लगाया गया है। इनके स्थानान्तरण के समय तक उक्त अभिलेख/संचिका कार्यालय में मौजूद थी, लेकिन इसमें **SDO** या **CO** द्वारा रद्दीकरण का कोई भी आदेश उपलब्ध नहीं था। ऐसी स्थिति में आज की तिथि में मूल अभिलेख अंचल कार्यालय में नहीं होने पर ये जवाबदेह नहीं है।

प्रतिवेदित आरोप, संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन एवं श्री कुमार के लिखित अभिकथन की सम्यक् समीक्षा की गयी। समीक्षा में पाया गया कि जहाँ तक आरोपी के द्वारा अंचल अधिकारी के रूप में समाहर्ता, गया के द्वारा जमाबंदी रद्द किये जाने से संबंधित आदेश की समीक्षा किये जाने प्रश्न है, इस प्रकार की शक्ति अंचल अधिकारी को प्रदत्त नहीं है। वर्ष 1994 में तत्कालीन समाहर्ता, गया द्वारा रद्द की गयी जमाबंदियों को वर्ष 2007 में अंचल अधिकारी के द्वारा बिना किसी तार्किक आदेश के बहाल किया जाना सही नहीं है। संचालन पदाधिकारी द्वारा जमाबंदी को रद्द किये जाने से संबंधित प्रदत्त शक्ति की समीक्षा अपने प्रतिवेदन में नहीं की गयी है। दूसरी तरफ आरोपी पदाधिकारी के द्वारा समाहर्ता, गया के वर्ष 1994 में दिये गये आदेश की समीक्षा किया जाना एवं उसे गलत प्रमाणित करने का प्रयास किया जाना गलत है। **Root Institute** के रद्द जमाबंदी को प्रारंभ करने में भी आरोपी पदाधिकारी श्री अनिल कुमार के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। इसके साथ ही किसी आवेदन-पत्र पर पृष्ठांकित आदेश के आलोक में रद्द की गयी जमाबंदी को प्रारंभ किया जाना भी गलत है। यदि इस प्रकार का कोई आदेश अंचल अधिकारी को प्राप्त हुआ, तो वैसी स्थिति में उन्हें अभिलेख संधारित कर रद्द जमाबंदी को पुनर्जीवित किये जाने हेतु प्रस्ताव समाहर्ता को भेजा जाना अपेक्षित था। रद्द की गयी जमाबंदी को प्रारंभ करने में आरोपित पदाधिकारी श्री अनिल कुमार के द्वारा विहित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। इन्होंने इस कृत्य का औचित्य तत्कालीन समाहर्ता के द्वारा **Root Institute** के आवेदन पर अंकित पृष्ठांकित आदेश को बताया है। अब इस मामले में की गयी अनियमितता और भी गंभीर प्रतीत होती है, क्योंकि **Root Institute** का वह कथित आवेदन एवं उस पर समाहर्ता का पृष्ठांकित आदेश अंचल कार्यालय की संचिका में उपलब्ध ही नहीं है, जिसके कारण आरोपित पदाधिकारी का कृत्य और भी संदेहास्पद कहा जा

सकता है। यह भी उल्लेखनीय है कि यदि उपर्युक्त आवेदन समाहर्ता के पृष्ठांकित आदेश सहित उपलब्ध हो भी जाये तो आरोपित पदाधिकारी के द्वारा उसके आधार पर जमाबंदी पुनर्जीवित करने हेतु की गयी कार्रवाई फिर भी नियमानुकूल नहीं कही जा सकती है।

श्री कुमार का यह आचरण उनके अनुशासनहीनता, स्वेच्छाचारिता एवं उच्चाधिकारियों के आदेश का अवहेलना को प्रदर्शित करता है। श्री कुमार का यह कृत्य आचार नियमावली, 1976 के नियम-3(1) के संगत प्रावधानों के प्रतिकूल है।

समीक्षोपरांत अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री कुमार के विरुद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के नियम-14 के संगत प्रावधानों के तहत **(i) निन्दन (आरोप वर्ष 2017-18) एवं (ii) संचयात्मक प्रभाव से दो वेतनवृद्धि पर रोक** का दंड अधिरोपित करने का विनिश्चय किया गया।

विभागीय पत्रांक 17176 दिनांक 14.12.2022 द्वारा श्री कुमार के विरुद्ध अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा विनिश्चित दण्ड प्रस्ताव पर बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से सहमति/परामर्श की मांग की गई। उक्त के आलोक में आयोग के पत्रांक 3568/लो0से0आ0 दिनांक 14.12.2022 द्वारा श्री कुमार के विरुद्ध विनिश्चित दंड प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त किया गया है।

अतएव अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार विनिश्चित दंड प्रस्ताव पर बिहार लोक सेवा आयोग से प्राप्त सहमति के आलोक में श्री अनिल कुमार (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 971/11, तत्कालीन अंचलाधिकारी, बोधगया सम्प्रति अपर समाहर्ता, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी के विरुद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-14 के संगत प्रावधानों के तहत निम्नलिखित दंड अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है।

(i) निन्दन (आरोप वर्ष 2017-18),

(ii) संचयात्मक प्रभाव से दो वेतनवृद्धि पर रोक।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधितों को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

शिवमहादेव प्रसाद,

सरकार के अवर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 54-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>